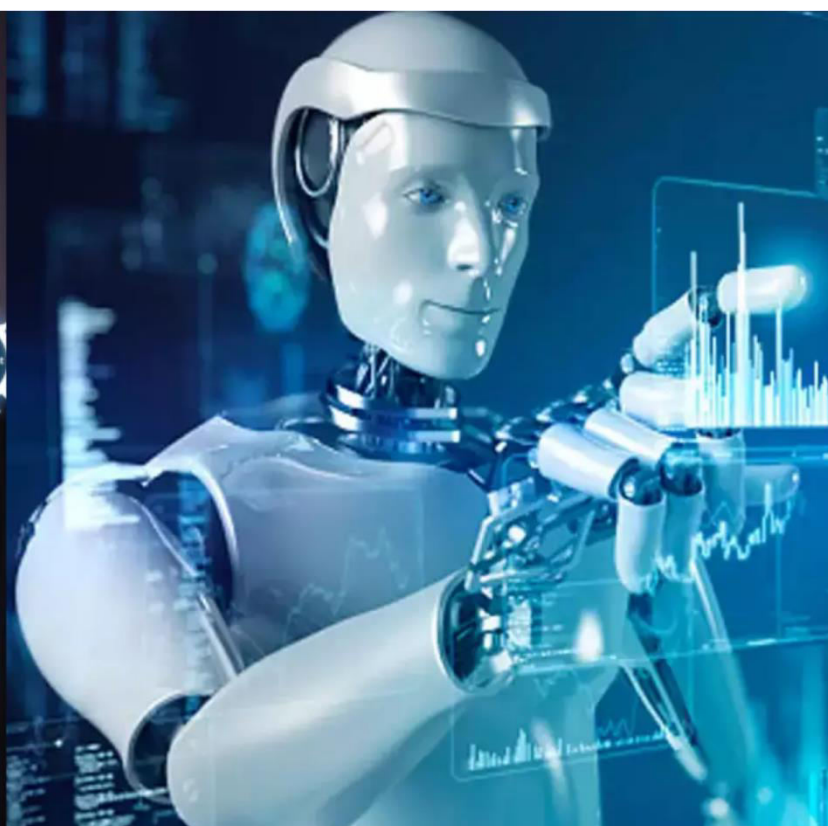




International Journal of Innovative Research in Science Engineering and Technology (IJIRSET)

(A Monthly, Peer Reviewed, Refereed, Scholarly Indexed, Open Access Journal)



Impact Factor: 8.699

Volume 15, Issue 3, March 2026

भारत में वित्तीय समावेशन पर डिजिटल भुगतान का प्रभाव

डॉ. सुनीता बेनीवाल

सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र)

राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर, झुंझुनू

सारांश

भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वित्तीय समावेशन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। हाल के वर्षों में डिजिटल तकनीक के विस्तार के साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिसने वित्तीय सेवाओं की पहुँच और उपयोग के स्वरूप को प्रभावित किया है। मोबाइल बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), डेबिट-क्रेडिट कार्ड तथा विभिन्न डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेन-देन की प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित और पारदर्शी हुई है। इसके परिणामस्वरूप पहले से वंचित या सीमित पहुँच रखने वाले वर्ग भी धीरे-धीरे औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ने लगे हैं। भारत में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक व्यक्ति नियमित रूप से भुगतान, बचत, ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाओं का सुरक्षित और सुविधाजनक उपयोग कर सके। डिजिटल भुगतान प्रणालियों के प्रसार ने इस लक्ष्य को व्यावहारिक रूप देने में नई गति दी है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर-आधारित भुगतान और कार्ड आधारित लेन-देन जैसे माध्यमों ने वित्तीय सेवाओं को घर-घर तक पहुँचाने की संभावना बढ़ाई है, विशेषकर उन वर्गों के लिए जो पहले दूरी, लागत या प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण औपचारिक बैंकिंग से दूर थे। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान के प्रसार तथा उसके वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली किस प्रकार बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता, उपयोगिता और पहुँच को प्रभावित करती है। साथ ही यह भी देखा गया है कि डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग से लेन-देन की पारदर्शिता, सुविधा तथा आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी किस प्रकार बढ़ी है।

मूल शब्द – डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेश, बैंकिंग प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी

परिचय :

समावेशी आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि समाज के सभी वर्गों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक समान और सुगम पहुँच प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए “वित्तीय समावेशन” की अवधारणा विकसित हुई है। वित्तीय समावेशन का आशय केवल बैंक खाता उपलब्ध कराने से नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि व्यक्ति नियमित रूप से बचत, ऋण, बीमा तथा भुगतान जैसी सेवाओं का सुरक्षित और सुविधाजनक उपयोग कर सके। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में लंबे समय तक बड़ी आबादी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर रही, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, निम्न आय वर्ग तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सीमित रही है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल तकनीक के प्रसार ने वित्तीय सेवाओं की संरचना और पहुँच में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब भुगतान और धन हस्तांतरण की प्रक्रिया अधिक सरल और त्वरित हो गई है। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने पारंपरिक नकद आधारित लेन-देन की तुलना में अधिक सुविधा और पारदर्शिता प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप छोटे व्यापारी, स्वयं सहायता समूह, किसान तथा आम उपभोक्ता भी धीरे-धीरे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने लगे हैं। इस परिवर्तन ने वित्तीय सेवाओं के उपयोग को दैनिक आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न नीतिगत पहलें की गई हैं। डिजिटल भुगतान के प्रसार ने बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया है तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच को आसान किया है। इसके माध्यम से छोटे और त्वरित लेन-देन संभव हुए हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है। साथ ही डिजिटल माध्यमों के उपयोग से भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ी है, जिससे औपचारिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है। हालाँकि डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार के बावजूद कुछ चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। डिजिटल साक्षरता का अभाव, तकनीकी अवसंरचना की सीमाएँ तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ अभी भी डिजिटल भुगतान के व्यापक उपयोग में बाधा उत्पन्न करती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इन समस्याओं का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इसलिए डिजिटल भुगतान के प्रभाव का अध्ययन करते समय इन अवसरों और चुनौतियों दोनों को समझना आवश्यक हो जाता है।

शोध के उद्देश्य :

1. डिजिटल भुगतान माध्यमों के उपयोग और वित्तीय समावेशन के बीच संबंध का विश्लेषण करना।
2. बैंक खातों के विस्तार और डिजिटल लेन-देन के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की पहुँच में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के उपयोग की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध प्राविधि :

प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार तथा उसके वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), वित्त मंत्रालय तथा नीति आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों से संबंधित आँकड़ों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न शोध-पत्रों, पुस्तकों तथा सरकारी दस्तावेजों का भी संदर्भ लिया गया है।

भारत में डिजिटल भुगतान का विस्तार :

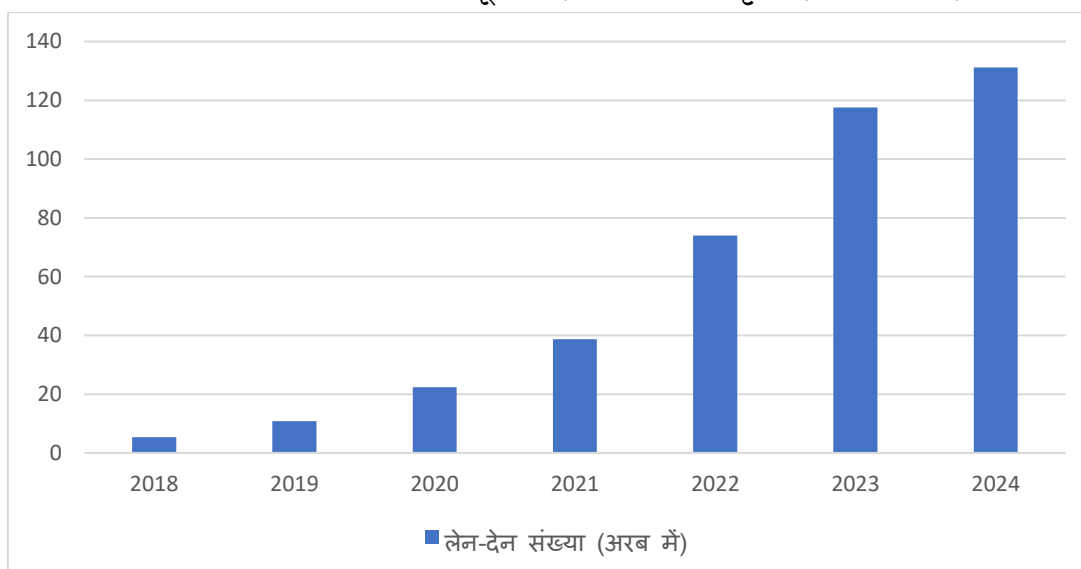
भारत में पिछले एक दशक के दौरान डिजिटल भुगतान प्रणाली का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास, स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग तथा इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता ने भुगतान प्रणाली को अधिक तेज, सरल और सुलभ बना दिया है। पहले जहाँ अधिकांश लेन-देन नकद माध्यमों पर आधारित थे, वहीं अब मोबाइल आधारित एप्लीकेशन, क्यूआर कोड तथा ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से धन का हस्तांतरण कुछ ही क्षणों में संभव हो गया है। इस परिवर्तन ने आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप को भी प्रभावित किया है और भुगतान प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाया है। सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें की गई हैं, जिनके परिणामस्वरूप डिजिटल लेन-देन में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। विशेष रूप से मोबाइल आधारित भुगतान प्रणालियों ने छोटे व्यापारियों, दुकानदारों तथा आम उपभोक्ताओं के लिए भुगतान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बना दिया है। इसके कारण डिजिटल भुगतान केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहकर छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी धीरे-धीरे पहुँच रहा है। इस प्रकार डिजिटल भुगतान का विस्तार भारत की भुगतान प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है, जिसने आर्थिक लेन-देन को अधिक पारदर्शी, त्वरित और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

तालिका 01 : भारत में यूपीआई लेन-देन की वृद्धि (2018–2024)

वर्ष	लेन-देन संख्या (अरब में)	लेन-देन मूल्य (लाख करोड़ रुपये)
2018	5.3	8.7
2019	10.8	17.3
2020	22.3	41.0
2021	38.7	71.5
2022	74.0	126.0
2023	117.6	182.8
2024	131.2	200 से अधिक

स्रोत : National Payments Corporation of India (NPCI). UPI Product Statistics

आरेख संख्या 01 : भारत में यूपीआई लेन-देन की वृद्धि (2018–2024)



उक्त तालिका में 2018 से 2024 के बीच भारत में यूपीआई आधारित डिजिटल लेन-देन की वृद्धि को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि इस अवधि में यूपीआई लेन-देन की संख्या और कुल मूल्य दोनों में निरंतर और तीव्र वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में जहाँ यूपीआई लेन-देन की संख्या लगभग 5.3 अरब थी, वहीं 2023 तक यह बढ़कर 117 अरब से अधिक हो गई। इसी प्रकार लेन-देन के कुल मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो इस अवधि में कई गुना बढ़ गया है। यह वृद्धि इस तथ्य को दर्शाती है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली अब भारत में व्यापक रूप से स्वीकार की जा रही है।

विशेष रूप से मोबाइल आधारित भुगतान एप और क्यूआर कोड प्रणाली के कारण छोटे और दैनिक लेन-देन भी डिजिटल माध्यमों से होने लगे हैं। इससे न केवल भुगतान प्रक्रिया सरल हुई है, बल्कि आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता और गति भी बढ़ी है।

बैंक खातों के विस्तार और वित्तीय समावेशन :

वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बैंक खातों की उपलब्धता एक बुनियादी और आवश्यक तत्व है। जब व्यक्ति औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ता है, तब उसे बचत, ऋण, बीमा तथा भुगतान जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने का अवसर मिलता है। भारत में लंबे समय तक बड़ी संख्या में लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए बैंक खाते तक पहुँच सीमित रही। पिछले कुछ वर्षों में बैंक खातों के विस्तार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस विस्तार ने समाज के विभिन्न वर्गों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंक खातों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ डिजिटल भुगतान के उपयोग ने इन खातों की सक्रियता को भी बढ़ाया है, जिससे वित्तीय सेवाओं का उपयोग अधिक व्यापक हुआ है। इस प्रकार बैंक खातों का विस्तार केवल वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने और आर्थिक गतिविधियों में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

तालिका 02 : प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत बैंक खातों की संख्या

वर्ष	खातों की संख्या (करोड़ में)	कुल जमा राशि (करोड़ रुपये)
2015	17.9	22,900
2017	30.1	65,800
2019	36.7	97,700
2021	42.2	1,46,200
2023	49.6	2,03,500
2024	51+	2,20,000 से अधिक

स्रोत : Ministry of Finance, Government of India. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, (PMJDY) Progress Report.

उक्त तालिका में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खुले बैंक खातों की संख्या तथा उनमें जमा राशि की स्थिति को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2015 से 2024 के बीच बैंक खातों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में जहाँ लगभग 17.9 करोड़ खाते थे, वहीं 2023-24 तक यह संख्या बढ़कर 50 करोड़ से अधिक हो गई। इसी प्रकार इन खातों में जमा कुल राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि इस बात का संकेत देती है कि बड़ी संख्या में लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ रहे हैं। बैंक खातों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ इन खातों में जमा राशि का बढ़ना यह दर्शाता है कि लोग केवल खाते खोल ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनका उपयोग भी कर रहे हैं।

डिजिटल भुगतान के प्रमुख माध्यम :

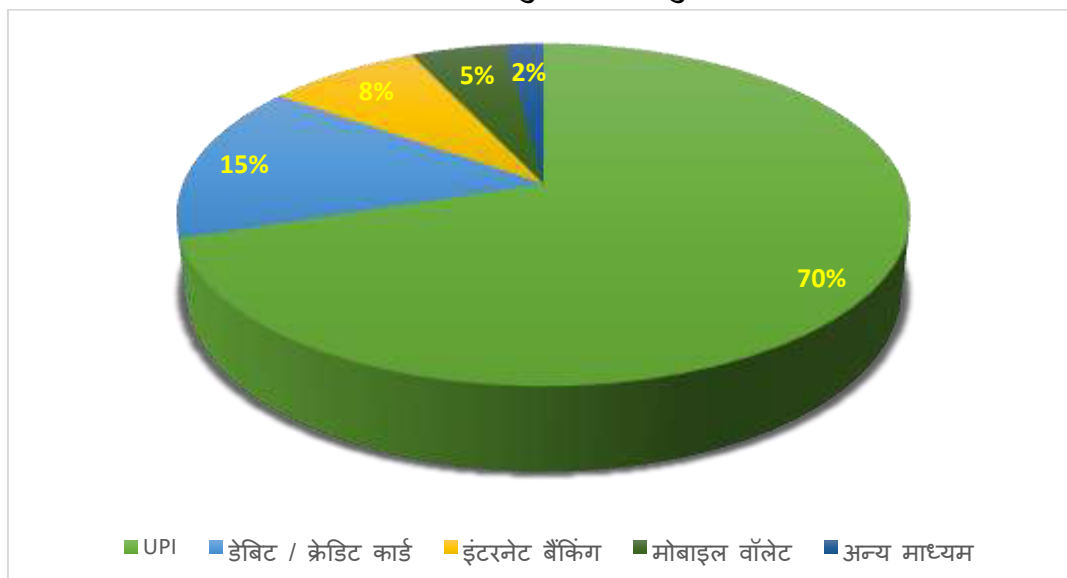
भारत में डिजिटल भुगतान कई माध्यमों से किए जाते हैं, जिनमें यूपीआई, कार्ड भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट प्रमुख हैं।

तालिका 03 : भारत में डिजिटल भुगतान के प्रमुख माध्यम (2024-25)

भुगतान माध्यम	कुल डिजिटल लेन-देन में अनुमानित हिस्सा (%)
यूपीआई	70 %
डेबिट / क्रेडिट कार्ड	15 %
इंटरनेट बैंकिंग	8 %
मोबाइल वॉलेट	5 %
अन्य माध्यम	2 %

स्रोत : Reserve Bank of India (RBI). Digital Payments Index and Payment System Indicators Report.

आरेख 02 : भारत में डिजिटल भुगतान के प्रमुख माध्यम (2024-25)



उक्त तालिका में भारत में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख डिजिटल भुगतान माध्यमों तथा उनके अनुमानित हिस्से को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि कुल डिजिटल लेन-देन में यूपीआई का योगदान सबसे अधिक है, जिसका हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत के आसपास है। इससे यह संकेत मिलता है कि मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली आज भारत में डिजिटल लेन-देन का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुकी है। इसके अतिरिक्त डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी महत्वपूर्ण है, जिनका कुल डिजिटल भुगतान में लगभग 15 प्रतिशत योगदान है। इंटरनेट बैंकिंग तथा मोबाइल वॉलेट का उपयोग अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है, फिर भी ये माध्यम ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान :

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार धीरे-धीरे सभी क्षेत्रों तक पहुँच रहा है, किन्तु इसके उपयोग में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कुछ अंतर दिखाई देता है। शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट, स्मार्टफोन और बैंकिंग सेवाओं की बेहतर उपलब्धता के कारण डिजिटल भुगतान का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल माध्यमों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, जिससे वहाँ भी डिजिटल भुगतान का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। हाल के वर्षों में मोबाइल आधारित भुगतान प्रणालियों और क्यूआर कोड जैसी सुविधाओं के कारण छोटे कस्बों और गाँवों में भी डिजिटल लेन-देन संभव हुआ है।

इससे न केवल भुगतान प्रक्रिया सरल हुई है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में सहायता मिली है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के विस्तार का अध्ययन वित्तीय समावेशन की स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

तालिका 04 : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान का उपयोग

क्षेत्र	डिजिटल भुगतान उपयोग (%)
शहरी क्षेत्र	72
अर्ध-शहरी क्षेत्र	55
ग्रामीण क्षेत्र	38

स्रोत : Reserve Bank of India (RBI). Report on Trend and Progress of Banking in India;
NITI Aayog. Digital Payments in India – A Status Report.

उक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है की शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान का उपयोग सबसे अधिक है, जहाँ लगभग 72 प्रतिशत लोग विभिन्न डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हैं। इसका मुख्य कारण वहाँ बेहतर इंटरनेट सुविधा, स्मार्टफोन की अधिक उपलब्धता तथा डिजिटल तकनीक के प्रति अधिक जागरूकता है। अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान का उपयोग लगभग 55 प्रतिशत के आसपास दिखाई देता है, जो यह दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग अपेक्षाकृत कम, लगभग 38 प्रतिशत है। इसके पीछे डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की सीमाएँ तथा तकनीकी संसाधनों की कमी प्रमुख कारण माने जा सकते हैं।

डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के प्रमुख प्रभाव:

वित्तीय समावेशन पर डिजिटल भुगतान के प्रभावों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत विश्लेषित किया जा सकता है-

1. बैंकिंग सेवाओं की पहुँच में वृद्धि - डिजिटल भुगतान प्रणाली ने बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को अधिक व्यापक बनाया है। पहले बैंक शाखाओं की सीमित संख्या और दूरी के कारण कई लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना कठिन होता था। मोबाइल आधारित भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से अब व्यक्ति बिना बैंक शाखा गए भी विभिन्न वित्तीय लेन-देन कर सकता है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना अधिक आसान हुआ है, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।

2. नकद लेन-देन पर निर्भरता में कमी - डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग से नकद आधारित लेन-देन पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है। डिजिटल माध्यमों के उपयोग से भुगतान प्रक्रिया अधिक त्वरित और सुरक्षित हो जाती है। इसके अतिरिक्त डिजिटल लेन-देन का रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ती है। नकद रहित भुगतान प्रणाली का विस्तार वित्तीय प्रणाली को अधिक संगठित और व्यवस्थित बनाने में सहायक होता है।

3. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार - डिजिटल भुगतान प्रणाली ने सरकारी योजनाओं के लाभों को लाभार्थियों तक सीधे पहुँचाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जा सकती है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक अधिक पारदर्शी तरीके से पहुँचता है।

4. छोटे व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र का औपचारिकीकरण - डिजिटल भुगतान के माध्यम से छोटे व्यापारी और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग भी औपचारिक आर्थिक प्रणाली से जुड़ने लगे हैं। आज छोटे दुकानदार, ठेला विक्रेता और सेवा प्रदाता भी डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। इससे उनके व्यवसाय की लेन-देन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होती है और वित्तीय रिकॉर्ड भी तैयार होता है। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे असंगठित क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सहायक बनती है।

5. महिलाओं और युवाओं की वित्तीय भागीदारी में वृद्धि - डिजिटल भुगतान प्रणाली ने महिलाओं और युवाओं की वित्तीय भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया है। मोबाइल आधारित बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से महिलाएँ स्वयं अपने खातों का संचालन कर सकती हैं और वित्तीय लेन-देन में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। इसी प्रकार युवा वर्ग डिजिटल तकनीक के उपयोग में अधिक सहज होने के कारण डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाता है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ती है और वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलती है।

निष्कर्ष :

भारत में डिजिटल तकनीक के प्रसार ने भुगतान प्रणाली के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। डिजिटल भुगतान के विभिन्न माध्यमों के विस्तार ने वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ, त्वरित और सुविधाजनक बना दिया है। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ने लगे हैं, जिससे वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को नई गति मिली है। विशेष रूप से मोबाइल आधारित भुगतान प्रणालियों और सरल डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से छोटे लेन-देन भी अब डिजिटल रूप में होने लगे हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल भुगतान ने बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए भी वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना पहले की तुलना में अधिक आसान हुआ है। साथ ही डिजिटल माध्यमों ने सरकारी योजनाओं के लाभों के वितरण को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया है। छोटे व्यापारियों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा महिलाओं की वित्तीय भागीदारी में वृद्धि भी डिजिटल भुगतान प्रणाली के सकारात्मक प्रभावों में शामिल है। हालाँकि डिजिटल भुगतान के विस्तार के बावजूद कुछ चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की सीमाएँ तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ कई क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के व्यापक उपयोग को प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इन समस्याओं का प्रभाव अधिक देखा जाता है। इसलिए वित्तीय समावेशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि डिजिटल अवसंरचना को मजबूत किया जाए, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए तथा सुरक्षित डिजिटल लेन-देन के प्रति लोगों में विश्वास विकसित किया जाए।

संदर्भ सूची :

1. Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank.
2. Government of India. (2023). *Economic Survey 2022–23*. Ministry of Finance, Government of India.
3. Ministry of Finance. (2024). *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: Progress Report*. Government of India.

4. National Payments Corporation of India. (2024). *UPI Product Statistics*. NPCI.
5. NITI Aayog. (2020). *Digital Payments in India: A Status Report*. NITI Aayog, Government of India.
6. Reserve Bank of India. (2023). *Report on Trend and Progress of Banking in India 2022–23*. RBI.
7. Reserve Bank of India. (2023). *Digital Payments Index (DPI) Report*. RBI.
8. Singh, S., & Rana, R. (2020). Study of consumer perception of digital payment modes. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 25(2), 1–14.
9. Kaur, P., Dhir, A., Singh, N., Sahu, G., & Almotairi, M. (2021). An innovation resistance theory perspective on mobile payment adoption. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 55, 102059.
10. Patil, P., & Sharma, S. (2022). Digital payment systems and financial inclusion in India. *International Journal of Financial Studies*, 10(3), 45–57.
11. World Bank. (2021). *Financial Inclusion Overview*. World Bank Group.
12. Reserve Bank of India. (2022). *Payment and Settlement Systems in India: Vision 2025*. RBI.
13. Suri, T., & Jack, W. (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. *Science*, 354(6317), 1288–1292.
14. Gupta, R., & Singh, A. (2023). Digital financial services and inclusive growth in India. *Journal of Asian Economics*, 86, 101512.
15. United Nations. (2022). *Digital Financial Inclusion and Sustainable Development*. United Nations Development Programme.



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details